भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 550
जिसका उत्तर 7 फरवरी, 2025 को दिया जाना है ।
18 माघ, 1946 (शक)

मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण क्षमता और इसके उपयोग की स्थिति

550. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण क्षमता का 50 प्रतिशत निष्क्रिय है और वर्ष 2024 में 500 मिलियन संस्थापित हैंडसेट विनिर्माण क्षमता में से वास्तविक उत्पादन केवल 250 मिलियन था;
(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का मत है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में सुधार किए जाने की आवश्यकता है;
(घ) सरकार मुख्य रूप से घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करने वाली छोटी कंपनियों, जो अपने असेंबली लाइनों के एक बड़े हिस्सा का टेलीकॉम और अन्य उत्पाद बनाने के लिए पुनः उपयोग कर रही हैं, के प्रति क्या दृष्टिकोण है; और
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार इसका समाधान किस प्रकार करेगी?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत सरकार की नीतियों के फलस्वरूप मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 60 मिलियन मोबाइल फोन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 330 मिलियन मोबाइल फोन हो गया है। पिछले 10 वर्षों में निर्मित मोबाइल फोनों की संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। मूल्य के संदर्भ में, मोबाइल फोनों का उत्पादन 2014-15 में मात्र 19,000 करोड़ रुपए की थोड़ी राशि से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 4,22,000 करोड़ रूपए का हो गया है, जो 41% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित सरकार की नीतियों के कारण, भारत 2014-15 में मोबाइल आयातक देश से अब मोबाइल फोन निर्यातक देश बन गया है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण ('एलएसईएम') के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से, मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 1,29,074 करोड़ रुपये हो गया है, जो 78% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। इसके अलावा, जहां 2015 में भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोनों का 74% आयात किया गया था वहीं भारत अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि जहां भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2% मोबाइल हैंडसेट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। *(स्रोत: उद्योग अनुमान)*

मोबाइल फोनों के विनिर्माण के अलावा, मोबाइल फोन की बैटरी, चार्जर, पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल, एनक्लोजर, यूएसबी केबल, फेराइट, ग्लास कवर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों/सब-असेंबलीज़ का निर्माण भी भारत में शुरू हो गया है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि देश में मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। मौजूदा घटक निर्माता अपनी मौजूदा क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और नए निवेशक भी भारत को एक संभावित बाजार की संभावना के रूप में देख रहे हैं।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना परिकल्पना के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दिसंबर 2024 तक, 10,213 करोड़ रुपये का संचयी निवेश, 6,62,247 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन और 1,37,189 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) सृजित हुए हैं। सरकार मुख्य रूप से घरेलू बाजारों के लिए उत्पादन करने वाले छोटे निवशकों के योगदान को भी मान्यता देती है। एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के तहत घरेलू मोबाइल फोन निर्माताओं ने 787 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया है, जिससे दिसंबर 2024 तक 34,111 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हुआ है और 25,288 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) पैदा हुए हैं। चूंकि इस योजना के अंतर्गत बेहतर काम हो रहा है, इसलिए इस योजना में वर्तमान में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है।

****